

आज

बेबाक

आतंकिस्तान के दहशतवादों द्वारा सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की थी। किन्तु इससे वहां के कट्टरपंथियों ने कोई सबक नहीं लिया और अब उन्होंने सिंध के एक मंदिर पर हमला कर वहां तोड़ फोड़ कर दी। एक हिन्दू लड़की को विवाह मंडप से उठाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह करा दिया। जाहिर है आतंकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर धर्म के आधार पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। अब जबकि भारत में नया नागरिकता कानून लागू हो चुका है तो वहां के अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने की कवायद शुरू हो जानी चाहिए।

खास खबर

पुलवामा शहीद के फंड में धांधली, योगी का ऐक्शन

आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए आगरा जिले के मुख्य विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए आगरा के कौशल कुमार रावत के परिजनों के जुटाए गए फंड के दुरुपयोग में सीडीओ को सस्पेंड किया गया है। इस बात की जानकारी सीएम कार्यालय द्वारा एक के बाद एक ट्वीट कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। जिला विकास अधिकारी पर पुलवामा आतंकी हमले में जनपद निवासी शहीद के परिजनों की मदद हेतु विभागीय कर्मचारियों द्वारा जुटाए गए चंदे की राशि के दुरुपयोग का आरोप था।

शक्तिशाली भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए युवा वर्ग - राज्यपाल टण्डन

भोपाल। राज्यपाल लालजी टंडन ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 8वें दीक्षांत समारोह में कहा कि युवा वर्ग शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज में अपनी रचनात्मक पहचान बनाना चाहिए। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि स्वावलम्बी बनना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और पूर्वजों की विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा में ज्ञान और विज्ञान का समावेश बढ़ता जा रहा है। युवाओं को इस परिवर्तन का लाभ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी स्वावलम्बी बन सकेगे और देश के नव-निर्माण में अपनी भूमिका निभा पायेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि युवा वर्ग मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के साथ समय के अनुकूल नवाचार भी किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बेटीयों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये पहले चरण में प्रदेश के 200 महाविद्यालयों को स्मार्ट कॉलेज बनाया जायेगा।

एनसीसी रैली / मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा- तीन-तीन जंग हार चुके पड़ोसी देश को हराने में हमें 10-12 दिन भी नहीं लगेंगे अन्याय को दुरुस्त करने के लिए लाया गया सीएए : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने और पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों से किए गए भारत के पुराने वादे को पूरा करने के लिए संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लेकर आई है। मोदी राष्ट्रीय कैडेट कार (एनसीसी) की सालाना रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता के समय से ही समस्या थी। कुछ परिवारों और

गांधीजी की इच्छा भी यही थी...

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दशकों पुरानी समस्याएं सुलझा रही उनकी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। मोदी ने कहा कि सीएए का विरोध ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने शत्रु सम्पत्ति कानून का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि जरूरत महसूस होने पर वे भारत आ सकते हैं। यही इच्छा गांधीजी की थी और यही भावना 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते की भी थी।

राजनैतिक दलों ने इसे जीवित रखा जिसके परिणामस्वरूप वहां आतंकवाद पनपा। उन्होंने एनसीसी कैडेटों से कहा कि उनकी सरकार देश को परेशान कर रही दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने और पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों से किए गए भारत के पुराने वादे को पूरा करने के लिए सीएए लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने सीएए के विरोध के संबंध में कहा कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक पर कब्जा करने की रस में लगे हैं। उन्होंने कहा,

ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के वास्ते भारत के पुराने वादे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सीएए लेकर आई है तो कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर इसका विरोध कर रहे हैं। “कश्मीर में कुछ लोग राजनीति करते रहे, तिरंगे का अपमान होता रहा और वे अपना वोट बैंक देखते रहे। 70 साल बाद कश्मीर से 370 हटया जा चुका है, ये हमारा दायित्व था। पाकिस्तान हमसे किसी भी जंग में नहीं जीता, इसलिए उसने बम धमाके और आतंकी हमले किए। भारत मां का खून बहता रहा, लेकिन जब सेना एक्शन के शेष पृष्ठ 7 पर

कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिना देश नहीं चलता : सीएम

इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग

परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग (मध्य क्षेत्रीय परिषद) नवा रायपुर स्थित एक होटल में शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। इस बैठक में चारों राज्यों के साथ उनके आंतरिक मुद्दों को लेकर सामंजस्य बनाने पर चर्चा की जाएगी। बैठक नवा रायपुर स्थित एक होटल में होगी। बैठक के बाद इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शेष पृष्ठ 7 पर



एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगुआई की

रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह समेत अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अगुआई के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर बुके देकर सबका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल समेत भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि चार राज्यों के सीएम इस बैठक के लिए आ चुके हैं। बैठक में केंद्र सरकार के साथ राज्यों के बीच और राज्य के आंतरिक मसलों पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में लिए गए फैसलों का एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इस बैठक में रखी जाएगी और समीक्षा होगी।

टकराव के कारण देश ठीक ढंग से नहीं चल सकता

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, इसका उदाहरण आज हम सब इस बैठक में देखेंगे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म (सहयोगी संघवाद) के बगैर देश चल नहीं सकता। देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बना रहे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कारण बनते हैं। इससे न केवल देश को हानि होती है, बल्कि देश ठीक ढंग से चल नहीं सकता।

बैठक में पहली बार शामिल हुए कमलनाथ

छत्तीसगढ़ में आयोजित नवसल प्रभावित राज्यों की इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली बार शामिल हुए थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि संघीय ढांचे में सतत संवाद जरूरी है और इसके लिए बैठकों में राज्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को बैठकों के निकषों पर राज्यों से चर्चा के बाद उस पर अमल करना चाहिए।

मालेगांव के पास रोडवेज बस कुएं में गिरी; 20 यात्रियों की मौत

यात्रियों ने बताया बस के सामने ऑटो रिकशा आने पर ड्राइवर ने नियंत्रण खोया

रोडवेज की बस नासिक से धुले जा रही थी, हादसे के वक्त 50 से ज्यादा यात्री सवार थे

नासिक। महाराष्ट्र में मालेगांव के पास मंगलवार शाम को महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (रोडवेज) की एक बस कुएं में गिर गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 को बचा लिया गया। नासिक ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया-हादसे के बाद 9 शव निकाले गए थे। 11 घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। बस नासिक से धुले जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि बस के सामने अचानक एक ऑटो रिकशा आ गया था। उसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस संतुलन खो गई। यात्रियों ने बताया कि बस कुएं में गिर गई। नासिक पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 20 लोगों की जान चली गई है। घायलों को मालेगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अपनी पूंजी बर्बाद कर रहा है 21वीं सदी का भारत: राहुल

जयपुर। जयपुर में आक्रोश रैली में बोलते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपीए के समय देश की विकास दर 9 फीसदी थी। वहीं, मोदी सरकार नए तरीके से जीडीपी नापती है तो विकास दर 5 फीसदी है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं

सदी का भारत अपनी पूंजी जाया कर रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमारी सरकार गरीबों को पैसा देती थी, जिससे अर्थव्यवस्था चलती थी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था तब चलती है, जब गरीबों के जेब में पैसा जाता है। जब उनकी जेब में पैसा जाता है तब वे माल खरीदते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों की जेब शेष पृष्ठ 7 पर

शायद देश मंदी के दौर में आंकड़े यही बोल रहे: बनर्जी

नई दिल्ली। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारत शायद मंदी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में तो ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस बात पर यकीन न हो। कोलकाता में एक साहित्यिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को बैंकिंग सेक्टर में पूंजी खालने पर जोर देना चाहिए, जो मुश्किल में चल रहा है। बनर्जी ने कहा, मैं यह कह सकता हूं कि यह मंदी का दौर हो सकता है।

लेकिन मैं नहीं कह सकता कि यह किताब है। आंकड़ों में ऐसा कुछ नहीं है जो यह बताए कि मंदी नहीं है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक बनर्जी ने इस बात की वकालत की कि धनी लोगों पर वेलथ टैक्स लगाया जाना चाहिए और धन का पुनर्वितरण होना चाहिए। बनर्जी ने कहा, भारत में मौजूदा असमानता के हालात को देखते हुए एक वेलथ टैक्स लगाना पूरी तरह से समझदारी वाली बात है। ऐसे हालात में ज्यादा पुनर्वितरण की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जल्दी होने वाला है।

प्रतिनियुक्ति रक्षा उत्पादन के अतिरिक्त सचिव बने बीएल कांताराव

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। 1994 बैच के आईएएस अफसर हरिरंजन राव के बाद अब 1992 बैच के अफसर वीएल कांताराव और नीलम शमी राव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। प्रमुख सचिव स्तर के दोनों अधिकारियों को कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति ने अतिरिक्त सचिव के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव को अतिरिक्त सचिव रक्षा उत्पादन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। वहीं, प्रमुख सचिव खाद्य नीलम शमी राव को महानिदेशक प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास एवं मंत्रालय बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राव दंपती केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए प्रयासरत थे। करीब डेढ़ माह पहले राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को केंद्र में सेवाएं देने के लिए सहमति भी दे दी थी। वीएल कांताराव की गिनती तेजतर्रार अधिकारियों में होती है। वहीं, नीलम शमी राव की छवि भी बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखने और अनावश्यक दबाव में न आने वाले



अधिकारी की रही है। जल्द होगा प्रशासनिक फेरबदल: सूत्रों का कहना है कि एक अपर मुख्य सचिव और चार प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की वजह से अब प्रशासनिक फेरबदल जल्द होगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग को अधिक समय तक प्रभार व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता है। वहीं, आईएएस अफसरों की नियमित पदोन्नति के बाद नए सिरे से पदस्थापना भी होना है। फरवरी-मार्च में कई अधिकारी प्रशिक्षण के लिए भी जाने वाले हैं। इसके मद्देनजर संभावना जताई जा रही है कि जिले से लेकर मंत्रालय स्तर पर फेरबदल होगा।

सीएए के खिलाफ बीजेपी विधायक, पार्टी बांट रही

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश की मंहर विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक नारायण त्रिपाठी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करते हुए कहा है कि कि सीएए से देश में गृहयुद्ध जैसी स्थितिवां बन रही हैं, जो देश के लिए घातक है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सीएए लागू करके देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी को भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को फाड़कर फेंक देना चाहिए और एक अलग से संविधान बनाकर उसके तहत देश को चलाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में नारायण त्रिपाठी ने कहा, जब मैंने महसूस



गई, पहली सूची में पार्टी ने केवल 33 जिलाध्यक्षों के नामों का ही ऐलान किया। 19 संगठनात्मक जिलों में नामों का ऐलान बाद में करने की बात कही गई, इसके पीछे वजह है बताया गया कि भोपाल, इंदौर सहित 19 जिलों में

बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ 19 जिलों में



अधिकारियों ने कहा कि खोजों
दलों को भूस्खलन की घटना में
भरे एक शब्द का शव मलबे से
मिला है। रिवरार और सोमवार को
बारिश थोड़ी कम हुई, जिससे
दमकलकर्मियों ने उद लोगों को
तलाश करने में मदद मिली।
जिनकी गुमशुदगी की सूचना मिली
थी, जब उनके घर बाढ़ में गल
थी। इस बीच, नान्दे जेरास
राज्य सरकार ने सोमवार को
मूसलाधार बारिश से प्रभावित
101 शहरों में आपातस्थिति
घोषित कर दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि भाजपा उन ऑटोदरिक्ता चालकों पर भारी जुर्माना लगाकर निशाना साध रही है, जिन्होंने अपने रियशों पर 'आई लव केजरीवाल' पेंट करा रखा है। राजधानी में एक ऑटोदरिक्ता चालक पर अपने ऑटोदरिक्ता पर 'आई लव केजरीवाल' लिखने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबर का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने भाजपा से गरीबी को निशाना बनाना बंद करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, "भाजपा अपनी पुलिस से गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान करवा रही है।"

सिंध(ए.)।पाकिस्तान में जबर्न
धर्म परिवर्तन कराने का एक और
मामला सामने आया है। विवाह
समारोह से एक हिंदू लड़की का
अपहरण कर उसका धर्म इस्लाम
में परिवर्तित कर दिया गया। उसके
बाद एक मुस्लिम शख्स से उसकी
शادی कराई गई। सिंध प्रांत के
मटियारी जिले में शनिवार को
लड़की को विवाह समारोह के
दौरान कुछ लोगों ने अपहरण कर
लिया। उसके बाद उसकी शادی
शाहरख गुल से कराई गई।
लड़की का नाम भारती बाई है।
अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं
के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की
है।

सभी जानते हैं कि कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मकसद सीएफ को समझना नहीं है। प्रवेश वर्मा यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तरह दिल्ली के एक कोने में भी आग लगी है। ये लोग आपके घर में घुसकर मारेंगे। मोदी नहीं होंगे तो ये लोग आपको काट डालेंगे। साथ ही उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान का भी समर्थन किया है। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि गद्गरी को गोली मारनी ही चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी नोटिस दे नहीं उरता हूँ। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्होंने नोटिस भी भेजा है। प्रवेश वर्मा ने कहा,

दिग्विजय ने कहा- सीएए, एनआरसी और एनपीआर भावनात्मक मुद्दे; इन्हें राजनीति से जोड़ना गलत

अदनान सामी को पदमश्री दे दिया, लेकिन कारगिल युद्ध लड़ने वाले को डिंटेशन कैप में डाल दिया

आईएसआई के साथ जासूसी करते भाजपा के बजरंग दल के नेता पकड़े गए, उन्हें जमानत दिलवा दी

नवप्रदेश संवाददाता
भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दे भावनात्मक हैं। इन मुद्दों को राजनीति से जोड़ना गलत है। देश के गृहमंत्री अमित शाह को प्रदर्शन कर रहे लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए और असल बात समझानी चाहिए। ये बात दिग्विजय सिंह ने आष्टा प्रवास के दौरान कही। सिंह यहां आष्टा के गांव बागेर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार आपको है, लेकिन इसमें



दोहरा मापडंड है। एक बहुत बड़े संगीतकार हैं अदनान सामी, जो पाकिस्तान के थे। इनके पिता ने पाक की एयरफोर्स में रहकर हिंदुस्तान पर बहुत बम फोड़े थे, उनको पीएम मोदी ने नागरिकता 2015 में दे दी।

यही नहीं, अब पंचश्री भी दे दिया। वही, आसाम के जिस मेजर सनाउल्ला खान ने कारगिल युद्ध लड़ा, तो उसे डिंटेशन कैप की जेल में बंद कर रखा है। यह दोहरा मापडंड है। यह भाजपा, मोदी और अमित

शाह का हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद है।

आईएसआई के साथ जासूसी करने वालों को जमानत क्यों दिलवा दी

दिग्विजय ने कहा कि भाजपा के राज में बेकसूर लोगों पर रासुका लगा दी जाती है। आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह पर अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। कहां गया- तुम्हारा राष्ट्रवाद। आईएसआई के साथ जासूसी करते भाजपा के बजरंग दल के नेता पकड़े गए, उन्हें जमानत दिलवा दी। जब यह बात बोलता हूं तो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही हैं।

आतंकियों के साथ पकड़े देवेंद्र को शेर-ए-कश्मीर का मैडल दिया

दिग्विजय ने कहा कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे क्यों नहीं पकड़ते। देवेंद्र सिंह ने

अफजल गुरु को मकान और गाड़ी किराए पर दिलवा दी, उसको भाजपा की सरकार ने शेर-ए-कश्मीर का मेडल दे दिया। जब नागरिकता का मसला आया तो यह हिंदू से मुसलमान, सिख, ईसाई से भी नागरिकता का प्रमाण मांगे। अगर कागजात में जरा भी खामी रही तो यह उन्हें डाउटफुल बना देगे।

भाजपा ने किसी का कर्ज माफ नहीं किया

दिग्विजय ने कहा- हमसे तो आप प्रश्न कर रहे हो शिवराज सिंह जी, लेकिन आप ने 15 साल तक राज किया। एक धेला किसी का माफ किया हो तो बता दो। इनको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर चुनाव लड़ते हैं। कोई ठेका ले लिया है क्या भाजपा ने हिंदुओं का। हम से बेहतर हिंदू कौन हो सकता है। ये वह भाजपा नेता हैं जिन्होंने नर्मदाजी की पैदल परिक्रमा की हो तो बता दो। शिवराजजी ने तो हेलीकॉप्टर से की।

भोपाल गैस त्रासदी : 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त धन के लिये केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करेगा कोर्ट

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये अमेरिका स्थित यूनिनयन कार्बाइड कार्पोरेशन की उत्तराधिकारी फर्म, अब इसकी मालिक डाउ केमिकल्स है, से 7,844 करोड़ की अतिरिक्त राशि दिलाने के लिये केन्द्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। जज अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ गैस पीड़ितों के लिये मुआवजे की राशि बढ़ाने की केन्द्र की सुधारात्मक याचिका पर विचार करेगी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनोद सरन, न्यायमूर्ति एम आर शाह और



न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट शामिल हैं। केन्द्र चाहता है कि गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिये पहले निर्धारित की गयी 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के अलावा यूनिनयन कार्बाइड और दूसरी फर्मों को 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन देने का निर्देश

दिया जाये।

तीन हजार से अधिक लोग मारे गये

यूनिनयन कार्बाइड कार्पोरेशन के भोपाल स्थित संयंत्र से दो-तीन दिसंबर, 1984 को एमआईसी गैस के रिसाव के कारण हुयी त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये

थे और 1.02 लाख लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुये थे। यूनिनयन कार्बाइड कार्पोरेशन ने इस त्रासदी के लिये मुआवजे के रूप में 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिये थे।

कारखाने से नहीं हटा जहरीला कचरा

सन 2012 में सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद भी यूनिनयन कार्बाइड कारखाने में दफन जहरीला कचरा राज्य की सरकारें हटवाने में आज तक नाकाम रहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन किया जाए, लेकिन कारखाने में दफन 350 टन जहरीले कचरे में से 2015 तक केवल एक टन कचरे को हटया जा सका है। इसे हटाने का ठेका रामको इन्वायरो नामक कंपनी को दिया गया

पारिवारिक कारणों से परेशान होकर आत्महत्या करने पहुंची महिला को गोताखोर ने बचाया

शीतल दास की बगिया में आत्महत्या करने पहुंची थी महिला

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। राजधानी के शीतल दास की बगिया में एक महिला आत्महत्या करने पहुंची बताया जा रहा है कि महिला पारिवारिक कारणों से परेशान होकर आत्महत्या करने पहुंची थी। आत्महत्या करने पहुंची महिला को देखकर मौके पर मौजूद गोताखोर आसिफ ने महिला को रोकते हुए डायल 100 को सूचना दी। सूचना मिलते ही श्यामला हिल्स थाना पुलिस पहुंची और महिला को थाने लेकर समझाइश दी। राजधानी के शीतल दास की बगिया में आत्महत्या करने पहुंची महिला का

नाम अनोता बताया जा रहा है। महिला नेहरू नगर की रहने वाली हैं। सूचना मिलते ही महिला के परिवार वाले भी श्यामला हिल्स थाने पहुंचे और महिला को अपने साथ घर ले गए। उधर राजधानी में डिंडोरी की एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर तीन महीने तक बंधक बनाकर तीन महीने तक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। किसी तरह से आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता भाग निकली। अपनी मां से संपर्क किया और थाने जाकर प्रकरण दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय किशोरी मूलत डिंडोरी की रहने वाली हैं। वह मजदूरी करती है और फिलहाल टीटी नगर थाने के पीछे निर्माणाधीन भवन में रहती है।

ऋण माफी



भोपाल (नवप्रदेश)। किसान कल्याण मंत्री सचिन यादव तथा पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी पत्र वितरित किए।

धारा 144

2 माह के लिए धारा 144 लागू, फेसबुक व्हाट्सएप पर पुलिस की नजर

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष या विरोध में कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति, धरना प्रदर्शन या रैली ना निकाले। धारा 144 लागू है। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप पर भी NRC और CAA के पक्ष या विरोध में पोस्ट ना डालें। पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर निगरा रखी जा रही। पोस्ट डालने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 14



क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। पुलिस द्वारा जनहित में जारी आदेश आगामी 2 माह तक लागू रहेंगे।

इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू

मध्यप्रदेश की राजधानी

भोपाल शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के किलोलपार्क, सिंधी कालोनी चैराहा, भोपाल टाकीज चैराहा, भारत टाकीज चैराहा, पीरगेट, जिन्सी चैराहा, लिली टॉकीज,

शब्वन चैराहा, रोयल मार्केट, अंबेडकर पार्क, सेकेण्ड स्टाप, बरखेड़ा पठानी, बिजली कालोनी, अशोकगार्डन, प्रदेश भाजपा कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, पर परंपरागत धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार की रैली, आम सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से 2 माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

2 माह तक प्रतिबंध

धारा 144 के आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित

क्षेत्रों में पुतला दहन, धरना प्रदर्शन आम सभा, रैली आंदोलन नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे। NRC/CAA के पक्ष या विरोध में प्रदर्शन को लेकर भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा यह आदेश भोपाल पुलिस जनहित में जारी किया गया है।

29 को भारत बंद। विधायक ने कहा – बंद का मैं समर्थन करता हूं

29 जनवरी को भारत बंद के ऐलान पर डीआईजी इश्राद वली ने

कहा कि जो भी भारत बंद में शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। विहित जगहों पर धारा 144 लागू है, धारा 144 महेनजर प्रदर्शन रैली को बंद करने नहीं है। जबर्न दुकानों को बंद करवाने पर कार्यवाई होगी। इधर, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 29 तारीख को भोपाल सहित भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि एनआरसी के विरोध में जो बंद हो रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही यह अपील करता हूं कि यह बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो। साथ ही लोग स्वेच्छ से इस बंद में शामिल हो।

रेडियो कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी पर चर्चा, शिक्षकों और बच्चों ने जाने तैयारी के टिप्स

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। सरदार वल्लभभाई पटेल सूरजनगर में रेडियो कार्यक्रम बच्चों को सुनाया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा 5 वीं, 8 वीं की इस वर्ष बोर्ड पैटर्न पर होने वाली वार्षिक परीक्षा के सम्बंध में बच्चों एवं शिक्षकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान परीक्षा की तैयारी संबंधी विशेष

वार्षिक परीक्षा के सम्बंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

टिप्स भी बच्चों को दिए गए। बता दें कि प्रदेश में पाँचवी और आठवीं कक्षा की आगामी वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में विशेष रेडियो कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी का 28 जनवरी यानि आज से प्रसारण शुरू किया गया। यह प्रसारण मध्यप्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी प्राथमिक एवं विविध भारती प्रसारण केन्द्रों से 11:30 से 12:00 बजे तक प्रसारित किया गया। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, आईईन सिंधिया जे.पी. ने सभी विभागीय मैदानी अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से कार्यक्रम सुनने तथा वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में विशेष अध्ययन-अध्यापन कार्य के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र के पाठ्यक्रम प्रभारी डॉ. अशोक पारिक और परीक्षा नियंत्रक के.पी.एस. तोमर, वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी पर चर्चा की। साथ ही अन्य शंकाओं का समाधान भी करेगे। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में किये गए संशोधन के बाद इस वर्ष से कक्षा 5वीं और 8वीं में पुनः वार्षिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। इन परीक्षाओं में असफल रहने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा में दूसरी बार पढ़ना होगा। इन परीक्षाओं के संबंध में विद्यार्थियों एवं उनके पालकों के मन में अनेक शंकाएँ एवं दुविधाएँ हैं, जिनका समाधान भी इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में बेहतर रिजल्ट के लिये परीक्षाओं की तैयारी, मॉडल पेपर्स का उपयोग, परीक्षा में आने वाला पाठ्यक्रम, लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के स्वरूप एवं परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्थाओं आदि बिंदुओं पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

न्यूज गैलरी

मार्ग में सरकारी मकान अलॉट करने में भी घोटाला, 96 मामले आए सामने

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी मकान अलॉट करने की प्रक्रिया में फजीवाड़ा का मामला सामने आया है. संपदा संचालनालय के एक बाबू द्वारा पैसे वसूलकर पुलिस वालों को नंबर आने से पहले ही मकान अलॉट करने की बात सामने आई है. यह फजीवाड़ा शिवराज सरकार के दौरान किया गया, लेकिन कमलनाथ सरकार में यह पकड़ में आया. बाबू राहुल खरते अब जेल में है. अब तक की जांच में 96 मामले पकड़ में आए हैं, जिन्हें समय से पहले सरकारी मकान अलॉट किया गया. सभी को नोटिस देकर मकान खाली कराए जा रहे हैं. सरकारी मकान अलॉटमेंट घोटाले में पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा मकान अलॉट कराए. जांच में 96 पुलिसकर्मियों के फजीवाड़े का खुलासा हुआ है. इस खुलासे के बाद संपदा संचालनालय ने उन सभी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो जल्द से जल्द मकान खाली करें. पिछले चार साल में पुलिस वालों को मकान अलॉट करने की जांच की जा रही है.

मकान खाली करने का नोटिस

इन कर्मचारियों को अगले महीने तक मकान खाली करना होगा. पिछले साल संपदा संचालनालय की जांच में सामने आया है कि गृह विभाग में पोस्टेड एक बाबू राहुल खरते ने मुख्यमंत्री की जाली नोटशीट बनाकर पुलिस वालों को सरकारी मकान अलॉट कर दिए. इस पर जहानाबाद पुलिस ने आरोपी खरते पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था. खरते जेल में बंद है.

दो साल में अलॉट मकानों की जांच में खुलासा

संपदा संचालनालय ने सबसे पहले 2018 और 2019 में पुलिस वालों को मकान अलॉट करने की जांच की. इसमें पता चला कि 2018 में 25 और 2019 में 66 मकान इस तरह फजीवाड़ा कर अलॉट किए गए. अब ऐसे मकान लेने वाले पुलिस कर्मचारियों को संपदा संचालनालय ने नोटिस जारी किए हैं. इन पुलिस वालों ने किस तरीके से आरोपी लिपिक खरते के साथ मिलकर मकान अलॉट कराए या किसी के कहने पर खरते ने ये मकान अलॉट किए थे. इन तमाम बिंदुओं पर अब विभाग जांच कर रहा है. विभाग ने तमाम जानकारी पुलिस को भेजी है. अब होगी जांचसाल 2018 और 2019 के अलॉटमेंट की जांच में ये धोखाधड़ी पकड़ी गई. संपदा संचालनालय अब पिछले 4 साल 2014 से 2017 के बीच पुलिस वालों को मकान अलॉटमेंट की जांच कर रही है. खरते लंबे समय से विभाग में पदस्थ था. इसलिए आशंका है कि मकान आवंटन में ये धोखाधड़ी काफी समय से चल रही होगी. संपदा गृह विभाग के अंतर्गत आता है. पता चला है कि खरते एक मकान अलॉट करने के 70 हजार से लेकर एक लाख या उससे ज्यादा पैसा वसूलता था.

सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई का नंबर

भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं होगी। दैनिक सुनवाई के लिए प्रस्तावित सूची में पदोन्नति मामले का नंबर नहीं आया है। अब इस मामले में जल्द सुनवाई का सरकार की ओर से आवेदन लगाया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति नियम 2002 निरस्त किए जाने की वजह से चार साल से पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। पदोन्नति में आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में बीते तीन साल से चल रहा है। सरकार की अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पदोन्नति से जुड़े एक अन्य प्रकरण में मध्यप्रदेश के मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित की थी। सरकार की ओर से इसके महेनजर सभी तैयारियां कर ली गई थीं, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई में पदोन्नति मामला शामिल नहीं हो पाया।

विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की तैयारी, राज्यों से मांगी जानकारी

भोपाल। राज्य के मंत्रियों का स्वेच्छानुदान बढ़ाए जाने के बाद विधायकों ने वेतन-भत्ता को लेकर भी सुगुबुगाहट तेज हुई है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने अन्य राज्यों में विधायकों को दिए जा रहे वेतन-भत्तों की जानकारी बुलाई है। इसके अध्ययन के बाद राज्य के विधायकों के मामले में निर्णय लिया जाएगा। वेतन-भत्ता बढ़ाए जाने की मांग विधायकों की लम्बे समय से रही है। इसके पीछे उनका तर्क है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए वेतन-भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाना चाहिए। पिछले दो विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मांग उठी रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे की अध्यक्षता वाली कमेट्री विधायकों के वेतन-भत्तों का अध्ययन कर रही है।

न्यायालय : श्रम न्यायालय , राजनांदगांव(छत्तीसगढ़)
प्रकरण क्रमांक 63/C.G.F.R.Act./2014
श्रवण तिथि 25.02.2020

विजय कुमार उजवने
आ. रामरक्षण उजवने
विरुद्ध
1. संभागीय प्रबंधक छ.ग. अयो. संरचना विकास निगम परिलखन प्रयाग संभागीय कार्यालय रायपुर छ.ग. एवं 01 अन्य

सूचना पत्र
आवेदन ने आपके विरुद्ध छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 31 (3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया है। अतएव आपको इस न्यायालय में पेशी तारीख 25.02.2020 को दिन में प्रातः 11:00 बजे प्रकरण का उत्तर देने के लिए हाजिर होने बाबत सूचित किया जाता है। आप न्यायालय में स्वतः या किसी ऐसे वकील द्वारा हाजिर हो सकते हैं, जिसे सत्यक अनुरोध किए गए हों, और जो इस प्रकरण से संबंधित सभी कार्रवायियों को उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि, आप उत्तर दिन सब दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जिन पर आपको प्रतिसादा आधारित हो।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे तो आपके की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि कार्रवायि उत्तर पेशी तारीख को अत्यंतता का कामकाज बंद रहता है तो आले के कार्यवाहक पर प्रकरण की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

PRESIOING OFFICER
LABOUR COURT
RAJNANDGAON (C.G.)

सुन

देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की जरूरत है, प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में योगदानयोग्य पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए कौशल उन्नयन पर ध्यान देना होगा। देश के लगभग 50 विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाना होगा ताकि युवा उच्चशिक्षा के लिए परदेस पलायन न करें और वे रोजगार प्रदाता बनें। कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े संसाधनों, उद्योग जैसे मत्स्यपालन, डेअर्री, जलोष्णीज उद्योग तथा फल-फूल की बागवानी इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। देश में लघु और कुटीर उद्योगों को सशक्त और प्रोत्साहन देने की जरूरत है, इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर लाभ देकर ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करना होगा। लाखों लोगों को रोजगार के अवसर की क्षमता रखने वाले टेक्स्टाइल, निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनफ्रास्ट्रक्चर, मैनुफैक्चरिंग उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

A portrait of a man with glasses and a clerical collar, likely a priest or bishop, looking directly at the camera.

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

A circular portrait of a woman with dark hair and a bindi on her forehead, looking slightly to the side.

पीते हैं जो
पीते हैं जो



- डॉ बिपिन पाण्डेय

References

एक ही सत्य जे
इतिहास॥ पावन
प्राणमय ,जय भ

कितना कु
सिमटता हृदय
उदासी सी अब
ही नहीं होती ह
एक एकाकीपन
अब सपने नह
जितनी तुमसे मि
तेरे न होने से।

भीत

- कमलकांत डोंगरे

युवा भारत में अब किसानों से ज्यादा बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2018 में प्रतिदिन औसतन 35 बेरोजगारों और अवरोजगारों से जुड़े 36 लोगों ने खुदकुशी की है। दोनो श्रेणियों को मिलाकर साल भर में 62,085 लोगों ने आत्महत्या की जिसमें कहना है कि संगठित क्षेत्र के बेरोजगार पैदा कर रहा है। नीचे की पोस्ट ऑटोमोबाइल के इन्फ्रस्ट्रक्चर और सार्वजनिक जीवन में रही नौकरियां खोल रहें। ऑटोमोबाइल क्षेत्र 35 के बेरोजगार देता है, वहीं टेक्नोलॉजी के बावजूद 10 करोड़ लोग

A large crowd of people, mostly men, are gathered in front of a building. Many of the people are holding up papers or documents, suggesting a protest or a public demonstration. The crowd is dense, and the people are looking in various directions, some towards the camera and others towards the building. The building in the background has a sign that reads "S.P.T." and some other text that is partially obscured. The overall atmosphere appears to be one of a significant public gathering.

गौरतलब है कि देश में जारी आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. और कम होती सैद्धांतिक मांग के चलते भारत में बेकारी की वृद्धि लगातार बढ़ने के कारण शिक्षित युवा बेरोजगारों की कतार लंबी होते जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिन हाथों में रोजगार था वे हाथ भी अब रोजगार विहीन हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 7.8 फीसदी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 5.3 फीसदी है। भारतीय श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार वाला देश है जहां साल 2019 के शुरुआत में ही 11 फीसदी आबादी यानि 12 करोड़ लोग रोजगार के कतार में हैं जिसमें 1.90 करोड़ संख्या ऐसे युवाओं की है जिनकी उम्र 25 वर्ष तक है, बेरोजगार युवाओं की बढ़ती

देश में बढ़ती बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध रोजगार के क्षेत्रों पर नजर डालें तो देश में संगठित, असंगठित और सरकारी क्षेत्र प्रमुख रूप से नौकरी प्रदाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा 10.1 फीसदी है, असंगठित क्षेत्र जिसमें कृषि भी शामिल है 60 फीसदी रोजगार उपलब्ध करता है। बदलते भारत में सरकारों ने कृषि की अपेक्षा औद्योगिक विकास को ज्यादा तरजीह दी, औद्योगिक विकास की बेरतनीब समक ने खेती की लाखों हेक्टेयर जमीन निगल ली लेकिन इसके बावजूद उद्योग देश की आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में नाकाम रहे। दरअसल आम भारतीय परिवार में आज भी सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण है। भारत में रेवेन्ने, सेना, पुलिस सहित विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के ज्यादा अवसर हैं, यही वजह है कि देश में सरकारी नौकरियाँ निकलने पर हजारों-लाखों लोग अर्जियाँ देते हैं। बेरोजगारी का अलम यह है कि सरकारी विभागों के निचले दरजे या निम्न स्तर पर सी या डी अथवा तृतीय-चतुर्थ ग्रेड के नौकरियों के लिए उच्च शिक्षित युवा जो इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., पी.एच.डी., पोस्टग्रेजुएट या अन्य उच्च शिक्षा डिग्रीधारी होते हैं वे भी इन नौकरियों के लिए अर्जियाँ देते हैं जबकि इन पदों की बुनियादी योग्यता महज आठवीं या दसवीं पास तथा सामान्य चलावने की क्षमता पर होती है। इन परिस्थितियों में

बोडोलैंड आंदोलन चलाने वाले संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते की जो पहल की है, वह स्वागतयोग्य है। हालांकि इस तरह का शांति समझौता हो पाना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने उपायविधियों से बाबरू की पहल करके हट्टु जो संसारलोक रुख दिखाया, उसी का नतीजा है कि एनडीएफबी जैसे खूंखार संगठन ने भी शांति और बातचीत के विकल्प को तबज्जो दी है।

संसाधनों पर आंच आने लगी, तो असंतोष पनपना स्वाभाविक था। समस्या तब और गंभीर होती गई जब आंदोलन का नेतृत्व भी कई धड़ों में बंटता चला गया और फिर अलग-अलग ग्रुपों ने हथियार उठाने को अंतिम विकल्प समझ लिया। ऐसे में सरकार किससे बात करे, या कौन सा धड़ा सरकार से बात करे, यह अविरोध नहीं रही। एक-दो धड़ों से बात होते हैं तो तीसरा उनके विरोध में आ जाता है और

मेधा को अपने मायके से आए हुए अमी एक घंटा ही हुआ था मिली। राधा- बहुत अच्छ किया बहू जो तू आ गई। तुम लोगों को

मिली राधा- बहुत अच्छा किया बहू जो तू आ गई तुम लोगों को बहुत याद कर रही थी। लगानागान एक घंटा अस्पताल में रुकने के बाद मेजा पे कफ़, अच्छा आँटी , बाद चल्ती रही। बहुत थकी हुई हूँ। आज सुबह ही मन्गी के घर से आई थी।उनकी भी तबियत खराब थी,इसलिए एक सप्ताह वहीं लग गया।भाई तो अमरीका में सर्फिस करता है। वह तो आ नही सकता था।तुझे ही उनकी देखभाल करनी थी। घर मों जी की तबियत खराब होने को समाचार आपने दिया तो अपने आपको कण नही पाईथकी होने के बावजूद आ गई।सोचा , लोग कहेंगे कि अपनी मन्गी की तबियत खराब थी तो एक हफ्ता रुक कर आई लेकिन मन्गी को देखने मनी निले गई। राधा ने सुना सत्त्व रह गई और बोली- बहू समय मिले तो फिर देखने आ जाना।जिन्दगी का क्या भरोसा?

नई दिल्ली | 1997 - महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1780 - भारत का पहला अंग्रेजी अखबार 'हिंदी गजट' या 'बंगाल गजट' प्रकाशित हुआ। 1916 - 'प्रथम विश्व युद्ध' में फ्रांस पर जर्मनी ने हमला कर हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया। 1939 - रामकृष्ण मिशन ने स्वतंत्र संस्थान की स्थापना। 1949 - ब्रिटेन ने जर्मनी पर पराजय का फैसला किया। 1953 - संतोषी नाटक 'अकादमी की स्थापना'। 1966 - अमेरिका के उत्तर-पूर्वी भाग में बर्फीले तूफान से 165 लोग मरे। 1970 - भारत के प्रसिद्ध गीतकार एन. एस. धीरू के देहांत। 1978 - राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म। 1978 - वायुमंडल की ओजोन परत पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण एयरोसोल से को प्रतिकर्षित करने वाला पहला देश स्वीडन बना।

5

चांदी महंगी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरो पर होने वाली बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण पीली धातु दुबाव में आयी है। फेड की दो दिवसीय बैठक 29 जनवरी को समाप्त होगी जिसके बाद मौद्रिक नीति पर बयान जारी किया जायेगा। विप्लेषकों का कहना है कि नोलेव कोरोना वायरस के बढ़ते के मामलों के कारण सोने को सम्पर्न मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाँदी हाजिर 0.02 डॉलर की गिरावट के साथ 18.02 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गयी।

न्यूज गैलरी

प्रदेश के नागरिकों की नींद हराम करना चाहते है शिवराज : अभय दुबे

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने जारी एक बयान में बताया है कि कितना शर्मनाक है कि भाजपा के एक हताश पूर्व मुख्यमंत्री न सिर्फ सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, अपितु वो उस आदेश में धार्मिक ध्वनीकरण भी देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000- 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सार्वजनिक स्थलों में विभिन्न स्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को अधिनियमित किया था। शोर नियम 2000 का नियम 5 लाउड स्पीकरों-सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2005 के फैसले में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, नागरिकों को सभ्य वातावरण में रहने का अधिकार है और उन्हें शांति से रहने का अधिकार है, रात में सोने का अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई जीवन के अधिकार गारंटी के लिए जो आवश्यक तत्व हैं तथा शोर नियम 2000 के सीधे सीधे उल्लंघन ने सुप्रीम कोर्ट को 18 जुलाई 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर ऐतिहासिक फैसला देने पर मजबूर किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी और जस्टिस अशोक भान की सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने लाउडस्पीकरों और हॉनों के यहां तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में पटाखों, लाउडस्पीकरों, वाहनों से उबर होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है। अदालत ने पाठ्य पुस्तकों में इस संदर्भ में शिक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया। अदालत ने सार्वजनिक स्थानों (आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर) रात 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिवराज जी अब आपका अराजक राज समाप्त हो चुका है। ये वर्तमान का आदेश सर्वोच्च अदालत के फैसले के दृष्टिगत लिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से राज्यों से नाराज था कि सही तरीके से राज्यों में उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश के हनुमान भक्त यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते है प्रदेश के नागरिक अपनी-अपनी धार्मिक आस्थाओं का भी पालन करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी।

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में 16 प्रकरणों पर हुई चर्चा

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में आज प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें बीते दिनों 26 जनवरी, 2020 को इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पार्टी विरोधी अनुशासनहीन कृत्य करने के कारण कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी चंद कुंजीर एवं देवेन्द्र सिंह यादव से सस्पेंशन दिये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। उक्त दोनों पदाधिकारियों को समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि सात दिवस में कार्यालय को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी से निष्कासित किये जाने की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। वहीं, एक दूसरे प्रकरण में आजाद सिंह डबास द्वारा राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णयों के संबंध में विपरीत टिप्पणी व्यक्त करने के कारण समिति ने इसे गंभीरतापूर्वक विचार कर डबास को उक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया है।

थप्पड़ मारने वाली कलेक्टर पर कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग, पार्टी ने जारी किया नोटिस

आजाद सिंह डबास ने सीएम कमलनाथ को कार्रवाई के लिए लिखी थी चिट्ठी

सीएम कमलनाथ को खत लिखना पड़ा भारी

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान देने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने अनुशासन का डंडा चलाया है। थप्पड़ मारने वाली राजगढ़ कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग करने वाले नेता को ही पार्टी ने निपटा दिया है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाए। इसके साथ ही इंदौर में एक-दूसरे को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अनुशासन समिति के लोगों ने अनुशासनहीनता के



राजगढ़ कलेक्टर पर की थी कार्रवाई की मांग

मामलों पर चर्चा की। जिसमें दो प्रमुख मुद्दे थे। इंदौर में सीएम कार्यक्रम से पहले कांग्रेसियों ने थप्पड़बाजी की थी। वहीं, राजगढ़ थप्पड़कांड पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सलाहकार कमिटी के संयोजक आजाद सिंह डबास के बयान पर भी चर्चा हुई।

कलेक्टर निधि निवेदिता पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि मंदसौर कलेक्टर की वजह से ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली गई थी। राजगढ़ कांड से सरकार की छवि खराब हुई है। उन्होंने लिखा था कि अधिकारी पूर्व में भी नंबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी पूर्व में घटित उन घटनाओं का भी जिक्र किया था, जिसकी वजह से प्रदेश में स्थिति बेकाबू हुई।

आजाद सिंह डबास के इस चिट्ठी को पार्टी ने अनुशासनहीनता का मामला माना है। अनुशासन समिति ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सलाहकार कमिटी के संयोजक पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न पार्टी

आपको बाहर का रास्ता दिखा दे। इसे लेकर उनसे जवाब भी मांगा है।

थप्पड़ चलाने वालों को नोटिस

वहीं, इंदौर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेता चंद कुंजी और देवेन्द्र यादव के बीच में थप्पड़बाजी हुई थी। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर थप्पड़ चलाई थी। उसके बाद पुलिस केस भी हुआ था। थप्पड़कांड का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई। उसके बाद अनुशासन समिति ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही उनसे कहा है कि आपको वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है।

कोरोना वायरस / पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी, भोपाल में हमीदिया अस्पताल में बनेगा आईसोलेशन वार्ड

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। उज्जैन में मरीज में कोरोना वायरस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में संदिग्ध मरीजों

इस बीमारी के लक्षण तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलना है

सुआब के सैंपल जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजने के निर्देश

के इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। इसकी तैयारी अस्पताल प्रबंधन ने शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त प्रतीक हजेला ने बताया कि सभी सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज डीन, जिला अस्पताल अधीक्षकों को कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के इलाज के लिए हॉस्पिटल में आईसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण मिलने पर मरीज के श्रोत के सुआब का सैंपल लेकर जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी हॉस्पिटल प्रमुखों को कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके इलाज की गाइडलाइन बताने ट्रेनिंग करने को कहा गया है। ताकि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिक्स को बीमारी का संक्रमण न हो। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज डीन को अस्पताल में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज और जांच की व्यवस्था रूटीन ओपीडी और आईपीडी से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बीमारी के मरीजों का इलाज करने वाले पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की टीम अलग से बनाने कहा गया है। ताकि बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।

मप्र में एक फरवरी से फिर शुरू होगा ठंड का दौर, बारिश के आसार

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भोपाल, उज्जैन व चंबल सभागों में सामान्य से अधिक एवं शेष सभागों के जिलों में सामान्य या सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल एवं जबलपुर सभागों के जिलों के कुछ हिस्सों में तथा ग्वालियर व चंबल सभागों में अगले 48 घंटों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं, 29 से 31 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। 30 जनवरी से उत्तरी ठंडी हवाएं पश्चिमी मप्र के



इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं होशंगाबाद सभागों के जिलों में पहुंच जाएगा। इससे न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। यानि कड़ाके की सर्दी वापसी कर सकती है। एक फरवरी से कड़ाके की ठंड का दौर फिर शुरू होगा। इधर, अगले 3-4 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 3 से 6 डिग्री

सेल्सियस की गिरावट और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलर बना हुआ है। इसके असर से मंगलवार से गरज-चमक के साथ हिराना, चंडीगढ़ और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।

भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने ही खोल दी, भाजपा और संघ के सांप्रदायिक एजेंडे की पोल : शोभा ओझा

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज जारी अपने वक्तव्य में बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा अपनी केन्द्र सरकार की विफलताओं को छिपाने के उद्देश्य से, छोटे-छोटे छद्म मुद्दों के सांप्रदायिकरण का प्रयास, देश के प्रति गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है, शिवराज सिंह ने आज अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो कुत्सित प्रयास किया है, वह प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के उस एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कहा जाएगा, जिसकी पोल आज भाजपा के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने खोल दी है। जारी अपने वक्तव्य में श्रीमती ओझा ने आगे कहा कि आश्र के मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने के



विषय में, शिवराज सिंह का ट्वीट धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास है, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और संघ को खुश करने के उद्देश्य से किया गया है। जबकि हकीकत यह है कि प्रशासन द्वारा पर पाबंदी लगाई गई है, जिसका किसी धार्मिक स्थल विशेष से कोई संबंध नहीं है, जैसा जिक्र शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में किया है। ओझा ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि शिवराज सिंह द्वारा उठाया

गया उपरोक्त मुद्दा हो या केन्द्र में मोदी व अमित शाह द्वारा उछाला गया सीएए और एनआरसी का मुद्दा हो, इन सभी छद्म मुद्दों की पोल देश की उस जागरूक जनता के सामने खुल चुकी है, जो अब यह समझने लगी है कि इन मुद्दों की आड़ में, गिरती जीडीपी, अवरूद्ध विकास, गरीबी, और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को दबाने का निंदनीय प्रयास किया जा रहा है। अपने बयान के अंत में श्रीमती ओझा ने कहा कि केवल आम जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के जागरूक लोग भी अब भाजपा सरकार की विभाजनकारी नीतियों के विरोधी हो गये हैं और अब धीरे-धीरे, वे अपने तानाशाही नेतृत्व के विरोध में मुखर होने को व्याकुल हैं, इसी का आगाज करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा के पक्ष में विभाजनकारी ताकतों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया है।

मिसाल तीन दिन पहले 10 साल के मयंक ने लिया था ब्रेन डेड मां के अंगदान कराने का फैसला

10 साल के बेटे का फैसला, अब मां की चिता की राख मिलाकर लगाऊंगा पौधे

23 जनवरी को उसकी मां दिशा सड़क हादसे का शिकार हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। चार दिन पहले हलालपुर के पास लो-फ्लो बस से उतरने के दौरान हुए हादसे में घायल हुई दिशा छवानी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें हमीदिया में भर्ती कराया गया था। दिशा को शनिवार सुबह डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, सड़क हादसे में उनके लिवर और



किडनी सहित दूसरे अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके चलते नेत्रदान ही हो पाया

था। मां के अंगदान करने का फैसला दिशा के 10 के साल बेटे मयंक छवानी का

था। अब उसने मां की चिता की राख मिट्टी में मिलाकर पौधे लगाने का निर्णय लिया है। बच्चे का यह साहसिक निर्णय देखकर रिन्ची समाज उत्थान पंचायत, विजय नगर के अध्यक्ष आनंद सबधाना का कहना है कि समाज के अन्य लोगों ने भी इस राख का इस्तेमाल पौधे लगाने में करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि मयंक यहां पर नीम, पीपल और तुलसी के 10 पौधे लगाएगा।

25 जनवरी को लिया था मां के अंगों को दान कर का फैसला

10 साल की उम्र में मयंक ने अपनी ब्रेन डेड मां के अंगदान करने का निर्णय

शनिवार को लिया था। मयंक ने कहा- मां के अंगों से कई लोगों को नया जीवन मिलेगा। मरने के बाद भी मां उसे देख सकेंगी। बता दें कि मयंक के पिता की मौत 7 साल पहले हो गई थी।

शनिवार सुबह डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया

लालघाट हलालपुर निवासी मयंक के पिता भीम छवानी की 8 जनवरी 2013 को ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मौत हो गई थी। भीम की पत्नी दिशा छवानी एक बुटीक पर काम करके अपने परिवार को भरण पोषण कर रही थीं। 23 जनवरी को हलालपुर, बीरआर्टीएस बस

स्टैंड पर बस से उतरते समय दिशा सड़क दुर्घटना का शिकार हुई। हमीदिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया। शनिवार सुबह डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है। बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। 23 जनवरी को दिशा सड़क हादसे का शिकार हुई। 24 जनवरी की रात उनकी सास मोहनी देवी का निधन हो गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंगदान के बाद दिशा का अंतिम संस्कार शनिवार शाम को होगा। अब परिवार और रिश्तेदार मयंक के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

भोज विश्वविद्यालय के कुलपति के गार्डन में दिखे बाघ के पगमार्क, पूरे कैंपस में अलर्ट जारी

वन विभाग की टीम को जो पगमार्क देखने मिले हैं वे करीब आठ से दस दिन पुराने बताए जा रहे हैं

विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाले सभी लोगों को एहितयात बरतने और अकेले नहीं जाने की समझाइश दी गई है

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। भोज विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुलपति जयंत सोनवलकर के घर के गार्डन में बाघ के पामार्क देखे गए हैं। मौके का



मुआयना करने गई वन विभाग की टीम ने पगमार्क अर्ध व्यस्क बाघ के होने की पुष्टि की है। वन विभाग ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम को जो पगमार्क देखने मिले हैं वे करीब आठ से दस दिन पुराने बताए जा रहे हैं। टीम ने पगमार्क बाघ के होने की पुष्टि की है। वन विभाग का कहना है कि ये पद चिन्ह किसी अर्धव्यस्क बाघ के हैं, जिसे उसकी मां ने अपने से दूर किया हो। एहितयात के तौर पर विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाले सभी लोगों को एहितयात बरतने और अकेले नहीं जाने की समझाइश दी गई है।

दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर कुलपति के निवास स्थित बगीचे में ये किसी जानवर के ये पगमार्क देखे गए हैं। विश्वविद्यालय की सूचना के बाद

ड्रोन की नई गाईड लाईन में प्रदेशों के सरोकार का ध्यान रखे केन्द्र: अभय दुबे

मध्यप्रदेश ने की प्रदेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जनसी सेंटर स्थापित करने की मांग

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने जारी एक बयान में बताया कि आज मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों की इंटर स्टेट कार्जिसल की बैठक में बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली भागीदारी सुनिश्चित की। इस बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की स्पष्ट मान्यता है कि संघीय ढाँचे में सतत संवाद जरूरी है। इस दृष्टिकोण से इन बैठकों का अपना महत्व होता है, मगर केंद्र को चाहिए कि ऐसी



बैठकों में निकलने वाले निष्कर्षों पर गंभीरता से राज्यों की मदद करें, तब ऐसी बैठकें और अधिक सार्थक सिद्ध होंगी। नक्सली समस्याओं के संदर्भ में एक लंबे अरसे से केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एक साझा रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। वैसे अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सली समस्या अधिक है, मगर मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती जिलों बालाघाट और मंडला में नक्सली मूवमेंट पाया जाता है। मगर हाल के वर्षों में नक्सली हमले

की कोई बड़ी वारदात मध्यप्रदेश में नहीं घटित हुई है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की मान्यता है कि मध्यप्रदेश की कुछ बुनियादी अपेक्षाएं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन को लेकर गाइडलाइन जारी की है, मगर उसमें राज्यों के सरोकारों को शामिल नहीं किया गया है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अर्थात काफी हद तक नक्सली समस्या से राज्यों को निपटना पड़ता है। ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।